इकाई 13 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का विकास

इकाई की रूपरेखा

13.0 उद्देश्य

13.1 परिचय

13.2 अनुसूचित जातियाँ कौन हैं?

13.3 अनुसूचित जातियों के लिए किए गए संवैधानिक प्रावधान

- 13.3.1 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत
- 13.3.2 सामाजिक सुरक्षा उपाय
- 13.3.3 शैक्षिक सुरक्षा उपाय
- 13.3.4 आर्थिक सुरक्षा उपाय
- 13.3.5 राजनीतिक सुरक्षा उपाय
- 13.3.6 सेवा सुरक्षा उपाय
- 13.3.7 अन्य सुरक्षा उपाय

13.4 अनुसूचित जातियों के सशक्तिकरण के किए गए उपाय

- 13.4.1 शैक्षिक विकास
- 13.4.2 आर्थिक विकास
- 13.4.3 सुरक्षात्मक उपाय

13.5 अनुसूचित जातियों का अन्य वर्गों के साथ एकीकरण

13.6 अनुसूचित जनजाति कौन हैं?

13.7 अनुसूचित जनजातियों के लिए संवैधानिक प्रावधान

- 13.7.1 संवैधानिक सुरक्षा उपाय
- 13.7.2 अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन
- 13.7.3 जनजातीय क्षेत्रों की सामाजिक–राजनीतिक स्वायत्तता

13.8 अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति

13.9 अनुसूचित जनजातियों के लिए किए गए अधिकारिता उपाय

- 13.9.1 जनजातीय विकास में राज्य की भूमिका
- 13.9.2 जनजातीय विकास खंड
- 13.9.3 जनजातीय उप–योजना
- 13.9.4 जनजातीय विकास के लिए नीतियां और कार्यक्रम

13.10 आदिवासियों के अनसुलझे मुद्दे और स्थायी समस्याएं

- 13.10.1आदिवासियों का विस्थापन
- 13.10.2जनजातीय भूमि हस्तांतरण

1.11 आइए हम सारांश करें

13.12 प्रमुख शब्द

13.13 सुझाई गई अध्ययन

13.0 उद्देश्य

इस इकाई का उद्देश्य आपको भारत में अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के विकास से परिचित कराना है। इस इकाई का अध्ययन करने के बाद आप :

- समझें कि एससी और एसटी कौन हैं;
- जानते हैं कि संविधान उन्हें विशेष रूप से क्या प्रदान करता है;
- आजादी के बाद उनके विकास के लिए किए गए उपायों से खुद को परिचित करा सकेंगे; और
- उन समस्याओं की पहचान करें जिनका वे समाज में सामना करते हैं।

13.1 परिचय

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, जो भारतीय समाज के सबसे वंचित और वंचित वर्गों का गठन करते हैं, ने ऐतिहासिक रूप से, उत्पीड़न, शोषण, पतन और अमानवीय व्यवहार के चरम रूपों का अनुभव किया है। अनुसूचित जाति उन जातियों या समूहोंध्समुदायों की एक श्रेणी का गठन करती है जो जाति व्यवस्था के भीतर मौजूद थे लेकिन सबसे कम सामाजिक रैंक के साथ थे जबकि अनुसूचित जनजाति उन समूहोंध्समुदायों की एक श्रेणी बनाती है जो जाति के दायरे से बाहर मौजूद हैं, हालांकि कुल अलगाव में नहीं। भारतीय समाज में इस ऐतिहासिक नुकसान ने उन्हें विकास के मामले में मुख्यधारा की जातियों और अन्य समूहों से बहुत पीछे कर दिया। स्वतंत्रता–पूर्व भारत में ब्रिटिश सरकार ने उत्थान के विशेष उपायों के लिए इनमें से कुछ जातियों और जनजातियों की पहचान की थी, लेकिन यह स्वतंत्र भारत का संविधान है जिसने धर्म, जाति, लिंग, पंथ या नस्ल के आधार पर सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त किया और विभिन्न सुरक्षा उपाय प्रदान किए। उनके संरक्षण और उत्थान के लिए। संवैधानिक प्रावधानों द्वारा निर्देशित भारत सरकार ने उनके विकास के लिए कई उपाय किए हैं। उनके विकास पर चर्चा करने से पहले आइए समझते हैं कि वे कौन हैं और उन्हें 'अनुसूचित जाति' और 'अनुसूचित जनजाति' का लेबल कैसे मिला।

13.2 अनुसूचित जातियाँ कौन हैं?

'अनुसूचित जाति' शब्द कई जाति समूहों को संदर्भित करता है जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से जाति व्यवस्था में सबसे निचले स्थान पर कब्जा कर लिया है जो भारतीय समाज की विशेषता है। सदियों से, वे अस्पृश्यता के बर्बर उपचार के अधीन होने के कारण, दयनीय दुख और गरीबी में रहते थे– जाति व्यवस्था की सबसे क्रूर विशेषताओं में से एक, जिसे कई लोग दुनिया में नस्लवाद के सबसे मजबूत रूप के रूप में देखते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय नेताओं के लिए अपनी सामाजिक–आर्थिक स्थिति में सुधार करना एक गंभीर मानवीय चिंता का विषय बन गया। संविधान ने अस्पृश्यता की प्रथा सहित सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त कर दिया। इसके अलावा, इन जातियों को विभिन्न सुरक्षा उपाय प्रदान करते हुए 'अनुसूचित जातियों' की संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई।

जाति व्यवस्था भारतीय समाज की एक विशिष्ट विशेषता है। यह 'शुद्धता–प्रदूषण' की धारणा के आधार पर समाज के एक पदानुक्रमित विभाजन को संदर्भित करता है। इसे धार्मिक प्रतिबंधों और विचारधारा के माध्यम से वैध बनाया गया है। वास्तव में, यह सामाजिक समूहोंध्जातियों के बीच श्रेणीबद्ध असमानता की एक प्रणाली है, जिसके सदस्यों को उनके जन्म के साथ–साथ उच्च या निम्न स्थिति प्राप्त होती है। एक जाति इस व्यवस्था का मूल घटक है।

प्राचीन भारत में समाज को शुरू में चार वर्णों या वर्गों में विभाजित किया गया था– ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। बाद में, यह वर्ण–विभाजन जन्म पर आधारित एक पदानुक्रमित संरचना में परिवर्तित हो गया। पुजारी और ज्ञान–प्राप्ति में लगे ब्राह्मणों ने पदानुक्रम में शीर्ष स्थान पर कब्जा कर लिया। उनके आगे 'क्षत्रिय' थे, जिन्होंने समाज पर शासन किया और आक्रमणकारियों से इसकी रक्षा की। तीसरा पद 'वैश्य' का था जिसने समाज के लिए खाद्य उत्पादन, व्यापार और धन की जिम्मेदारी ली। 'शूद्रों' का स्थान निम्नतम था। उनमें से अधिकांश खेतिहर मजदूर या गुलाम थे। इनमें कारीगर, शिल्पकार, कलाकार, नर्तक और संगीतकार भी शामिल थे। समय के साथ, इस वर्ण पदानुक्रम की गतिशीलता ने कई जातियों का निर्माण किया जो हजारों जातियों के पदानुक्रम में परिणत हुई। हालांकि 'जाति', 'वर्ण' नहीं, लंबे समय से भारतीय समाज की एक वास्तविकता रही है, जाति व्यवस्था की अनूठी विशेषताओं और जटिल गतिशीलता को समझने का प्रयास करते हैं, उन्हें पदानुक्रमित रूप से व्यवस्थित करने के लिए वर्ण योजना का उपयोग किया है।

कुछ विद्वानों ने इसकी उत्पत्ति के लिए विभिन्न नस्लों या जनजातियों के अस्तित्व को जिम्मेदार ठहराया है, जिन्हें बाद में विभिन्न जातियों के रूप में जाना जाने लगा। यह माना जाता है कि भारत में सामाजिक पदानुक्रम नस्लीय शुद्धता की धारणा पर आधारित था। कालान्तर में कालांतर में यह धारणा अनुष्ठान शुद्धता में बदल गई और धार्मिक स्वीकृति के माध्यम से और अधिक मजबूत हुई।

दूसरी ओर, कई विद्वानों का मत है कि समाज की भौतिक आवश्यकताओं के कारण श्रम का विभाजन हुआ जो बाद में वंशानुगत व्यवसायों के आधार पर सामाजिक भेदभाव का कारण बना। वंशानुगत व्यवसायों की प्रथा अंततः विभिन्न जातियों के रूप में समेकित हुई।

बौद्ध धर्म के उदय ने कर्मकांडीय शुद्धता–अशुद्धता पर आधारित जातियों की पदानुक्रमित व्यवस्था पर गंभीरता से सवाल उठाया और ब्राह्मणवादी व्यवस्था के आधिपत्य को चुनौती दी। इस चुनौती का सामना करने के लिए, विभिन्न संस्कारों के निर्माण और समर्थन के मिथक से लैस मनु ने वर्ण व्यवस्था की प्राचीन व्यवस्था को फिर से स्थापित करने का प्रयास किया। मनुस्मृति बौद्ध धर्म के खिलाफ ब्राह्मण अभिजात वर्ग की नाराजगी को दर्शाती है। इस आक्रोश में महिलाएं और शूद्र मुख्य शिकार बने। मनु ने इस बात पर जोर दिया कि शूद्रों का मुख्य पेशा 'द्विज' लोगों–ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों की सेवा करना था।

आजादी के बाद, छुआछूत की प्रथा को रोकने के लिए अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955, बनाया गया था। 1976 में संशोधित, इसने अस्पृश्यता को एक संज्ञेय अपराध बना दिया। संशोधित अधिनियम को नागरिक अधिकारों के संरक्षण अधिनियम, 1955 के रूप में जाना जाता है। हालाँकि, छुआछूत अभी भी स्पष्ट रूप से या गुप्त रूप से व्यवहार में है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ निचली जातियों को विभिन्न प्रकार के

भेदभाव का सामना करना पड़ता है। बहरहाल भारतीय राज्य अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसलिए, इस इस प्रथा में गिरावट आ रही है।

'अनुसूचित जाति', हालांकि मूल रूप से एक संवैधानिक अवधारणा है, शुरुआत में इसे कानूनी और प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा कानूनी और प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए गढ़ा किया गया था अप्रैल 1936 में, ब्रिटिश सरकार ने एक आदेश जारी किया जिन्हें पहले दलित वर्गों के रूप में जाना जाता था। सामाजिक–आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए, स्वतंत्र भारत ने अनुसूचित जातियों के लिए संविधान में विशिष्ट प्रावधान किए। संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 परिभाषित करते हैं कि

किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में कौन अनुसूचित जाति होगी। अनुच्छेद 341 (1) में कहा गया है, ''राष्ट्रपति, किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में और जहां यह एक राज्य है, सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा उसके राज्यपाल से परामर्श के बाद जातियों, मूलवंशों या जनजातियों या जातियों के भीतर या समूहों को निर्दिष्ट कर सकता है। , जाति या जनजाति, जो इस संविधान के प्रयोजनों के लिए, उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में अनुसूचित जाति समझा जाए।

अनुच्छेद 341 (2) सूचित करता है, ''संसद, कानून द्वारा, खंड (1) के तहत जारी अधिसूचना में निर्दिष्ट अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल या बाहर कर सकती है, किसी भी जाति, नस्ल या किसी जाति के भीतर या समूह का हिस्सा, नस्ल या जनजाति, लेकिन जैसा कि पूर्वोक्त को छोड़कर, उक्त खंड के तहत जारी की गई अधिसूचना किसी भी बाद की अधिसूचना से भिन्न नहीं होगी''।

समय–समय पर संवैधानिक अनुसूचित जाति आदेश, 1950, समय–समय पर संशोधित, उल्लेख करता है कि हिंदू या सिख धर्म से अलग धर्म को मानने वाले किसी भी व्यक्ति को अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जा सकता है। हालांकि, अनुसूचित माने जाने के लिए कोई धार्मिक प्रतिबंध नहीं है हल ही में, आरक्षण का लाभ उन अनुसूचित जातियों को भी दिया गया है जिन्होंने बाद में अपना धर्म बदल लिया है और बौद्ध धर्म को स्वीकार किया है।

आइए अब अनुसूचित जातियों के लिए किए गए संवैधानिक प्रावधानों पर चर्चा करें।

13.3 अनुसूचित जातियों के लिए संवैधानिक प्रावधान

संविधान अनुसूचित जातियों के हितों के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं:

13.3.1 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत

संविधान में, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के तहत अनुच्छेद 46 व्यापक रूप से विकासात्मक और नियामक दोनों तरह के निर्देशों का पालन करता है। इसमें लिखा है, ''राज्य लोगों के कमजोर वर्गों और विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को विशेष सावधनी के साथ बढ़ावा देगा, और उन्हें सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से बचाएगा।

13.3.2 सामाजिक सुरक्षा उपाय

संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके अभ्यास पर रोक लगाता है।

अनुच्छेद 23 मानवों के अवैध व्यापार और जबरन श्रम या 'बेगार' पर रोक लगाता है। बंधुआ मजदूरी जबरन मजदूरी का एक चरम रूप है और अधिकांश बंधुआ मजदूर अनुसूचित जाति के हैं।

अनुच्छेद 25 (2) (बी) अनुसूचित जाति को किसी भी संप्रदाय के सभी मंदिरों में प्रवेश प्रदान करता है।

अनुच्छेद 15 (ए) दुकानों, रेस्तरां, टैंकों, स्नान घाटों, सड़कों, सार्वजनिक सुविधा के स्थानों आदि तक पहुंच के संबंध में किसी भी विकलांगता, प्रतिबंध या शर्त को हटाने का प्रावधान करता है।

13.3.3 शैक्षिक सुरक्षा उपाय

अनुच्छेद 15(4) शैक्षणिक संस्थानों में स्थानों के आरक्षण, छात्रवृत्ति आदि के रूप अनुसूचित जातियों की शैक्षिक उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करता है।

अनुच्छेद 29(2), सामान्य तौर पर, राज्य द्वारा अनुरक्षित शैक्षिक संस्थनों या राज्य निधियों से अनुदान प्राप्त करने वालों तक उनकी पहुंच की रक्षा करता है।

13.3.4 आर्थिक सुरक्षा उपाय

संविधान राज्य को अनुसूचित जातियों के आर्थिक हितों को विशेष सावधानी के साथ बढ़ावा देने और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से बचाने का आदेश देता है।

13.3.5 राजनीतिक सुरक्षा उपाय

संविधान के अनुच्छेद 330, 332 और 334 में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विशेष प्रतिनिधित्व का प्रावधान है। राजनीतिक आरक्षण की अवधि शुरू में दस साल के लिए कल्पना की गई थी। हालाँकि, इसे दस वर्षों के अंतराल पर बार–बार बढ़ाया गया है।

13.3.6 सेवा सुरक्षा उपाय

अनुच्छेद 16(4) पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के पक्ष में सेवाओं में आरक्षण प्रदान करता है जिनका उनमें अपर्याप्त प्रतिनिधित्व उनमें अपर्याप्त है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि 'पिछड़ा वर्ग' संविधान में अपनाया गया एक सामान्य शब्द है, जिसमें एससी और एसटी भी शामिल हैं। अनुच्छेद 335 में प्रावधान है कि सरकारी सेवाओं और पदों पर नियुक्तियां करने में अनुसूचित जातियों (अनुसूचित जनजातियों पर भी लागू) के सदस्यों के दावों को लगातार प्रशासन की दक्षता बनाए रखने के साथ ध्यान में रखा जाएगा।

13.3.7 अन्य सुरक्षा उपाय

संविधान के अनुच्छेद 338 में कहा गया है कि ''अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाने वाला एक विशेष अधिकारी होगा''। इसके अनुसरण में, केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित

जनजाति के लिए एक आयुक्त नियुक्त किया जाना आवश्यक है। आयुक्त संविधान के तहत उनके लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच करता है।

इससे पहले कि हम अनुसूचित जातियों के लिए किए गए सशक्तिकरण उपायों पर चर्चा करें, मैं आपकी प्रगति की जांच करता हूं।

13.4 अनुसूचित जातियों के सशक्तिकरण के लिए उपाय

अनुसूचित जाति अपने सामाजिक–आर्थिक पिछड़ेपन के कारण बाकी समाज से पिछड़ गई है। इसलिए उनका आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण देश के विकास एजेंडे पर प्राथमिकता बना हुआ है। वे कुल आबादी का एक बड़ा हिस्सा बनाते हैं, यानी 20,13,78,086 करोड़ या 16.6 प्रतिशत (जनगणना 2011)। अनुसूचित जाति की कुल आबादी में से 18.5 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। अकेले उत्तर प्रदेश में भारत की कुल अनुसूचित जाति आबादी का 20 प्रतिशत से अधिक है।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों की देखरेख करने के लिए नोडल मंत्रालय है। यह शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के प्रयासों को पूरा करने के लिए कार्यक्रमों को लागू करने के अलावा अनुसूचित जातियों के हितों के संरक्षण और संवर्धन के लिए राज्यध्केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों और अन्य केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा की गई कार्रवाई की निगरानी करता है। कुछ विकासात्मक योजनाएँ नीचे दी गई हैंः

13.4.1 शैक्षिक विकास

अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति (पीएमएस) अनुसूचित जातियों के बीच उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए देश में अपनी तरह की सबसे बड़ी शैक्षिक योजना है।

अन्य योजनाओं में अस्वच्छ व्यवसायों के काम करने वाले लोगो के बच्चों के लिए प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति, अनुसूचित जाति के लड़कों और लड़कियों के लिए छात्रावास, बुक बैंक, मेरिट का उन्नयन और अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए कोचिंग और संबद्ध योजनाएं हैं।

इसके अलावा, कमजोर वर्गो के मेधावी विद्यार्थियों को उच्चतर अध्ययन करने के लिए पहचानने, बढ़ावा देने और सहायता प्रदान करने के लिए वर्ष 2002–03 से मेधवी अनुसूचित जातिध/नुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय छात्रवृत्ति शुरु की गई हैं।

13.4.2 आर्थिक विकास

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित एवं विकास निगम (एनएसएफडीसी) और राष्ट्रय सफाइ कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (एनएसएफडीसी) तथा राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम अनुसूचित जातियों से संबंधित के लिए क्रमशः राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहें हैं।

इसके अलावा, अनुसूचित जातियों के लिए अन्य महत्वपूर्ण आर्थिक विकास योजनाएं निम्नलिखित हैंः

- अनुसूचित जातियों के लिए ऋण वृदधि गारटी योजना (सीईजीएसएससी)
- अनुसूचित जाति उप–योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता (एससीएसपी को एससीए)
- अनुसूचित जाति विकास निगमों (एससीएसपी को सहायता की योजना मैला ढोने वालों के पुन वीस के लिए स्वररोजगना (एसआरएमएस)

13.4.3 सुरक्षात्मक उपाय

नागरिक अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1955 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 अस्पृश्यता को समाप्त करने और अनुसूचित जाति पर अत्याचार को रोकने के लिए उठाए गए विधायी उपाय हैं। मैला ढोने वालों के रोजगार का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 अस्वच्छ शौचालयों और मैला ढोने की प्रथा को खत्म करने और वैकल्पिक व्यवसायों में मैला ढोने वालों का पुनर्वास करने के लिए एक कड़ा कानून है जो सरकार की उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र रहे हैं। इसके अलावा, सरकार ने सामान्य रूप से अनुसूचित जाति और विशेष रूप से मैला ढोने वालों के हितों की रक्षा के लिए निम्नलिखित विशेष कल्याणकारी उपाय किए हैं और विशेष एजेंसियों का गठन किया है।

अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना और विशेष केंद्रीय सहायता का विशेष तंत्र

1979–80 में पेश किया गया, यह अनुसूचित जातियों के समग्र विकास के लिए संसाधनों का समान हिस्सा सुनिश्चित करने का सबसे प्रभावी साधन है। केंद्रीय बजट सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित विभिन्न परियोजनाओं और योजनाओं पर खर्च करने के लिए धन आवंटित करता है, जिसका उद्देश्य अपने लक्ष्य समूहों– एससी, एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) का सर्वांगीण विकास– आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक सशक्तिकरण करना है।

- **बीस सूत्री कार्यक्रम**

शुरुआत में इसे 1975 में लॉन्च किया गया था। नई नीतियों और कार्यक्रमों की शुरुआत के साथ इसे अंततः 2006 में पुनर्गठित किया गया था। वर्तमान में यह संचालन में है। इसका बिंदु संख्या 11 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को न्याय प्रदान करता है। इसके अलावा, संख्या 7(3), 14(3) और 16(2) जैसे बिंदु अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विकास पर विशेष ध्यान देने का प्रावधान करते हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय बिंदु संख्या 11 (ए) की निगरानी के लिए नोडल एजेंसी है।

- **विशेष घटक योजना (एससीपी)**

अनुसूचित जाति के समग्र विकास को प्राप्त करने और गरीबी रेखा से ऊपर उनकी आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के लिए 1979–80 में शुरू किया गया, एससीपी अनुसूचित जाति के विकास के लिए राज्योंध्केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रालयों की योजनाओं में सामान्य क्षेत्रों से परिव्यय और लाभ के प्रवाह को चौनलाइज करता है। सामान्य योजना से विशेष घटक योजना के लिए निधियों के प्रवाह का अनुपात कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के अनुपात से कम नहीं होना चाहिए। एक छत्र कार्यक्रम होने के नाते केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित सभी

योजनाओं को अनुसूचित जाति के लोगों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जोड़ा गया है।

- **विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए)**

अनुसूचित जाति उप–योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता, एक केंद्र प्रायोजित योजना, 1980 में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जाति के आर्थिक विकास की परिवार–उन्मुख योजनाओं पर जोर देने के लिए शुरू हुई। इसके तहत, राज्योंध्केंद्र शासित प्रदेशों को उनकी अनुसूचित जाति उप–योजना (एससीएसपी) के अतिरिक्त 100ः अनुदान दिया जाता है।

- **अनुसूचित जाति विकास निगमों (एसडीसी) को सहायता**

अनुसूचित जाति विकास निगमों (एससीडीसी) की शेयर इक्विटी में 49:51 के अनुपात में भाग लेने के लिए यह केंद्र प्रायोजित योजना 1979 में शुरू की गई थी। वर्तमान में 23 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यरत दोनों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। उनके मुख्य कार्यों में पात्र परिवारों की पहचान करना और उन्हें आर्थिक विकास योजनाएँ चलाने के लिए प्रेरित करना, वित्तीय संस्थानों को ऋण सहायता के लिए योजनाएँ प्रायोजित करना, प्रपत्र में वित्तीय सहायता प्रदान करना शामिल है। ताकि इसे कम किया जा सकें। चुकौती देयता को कम करने और अन्य सम्पति अपशमन कार्यक्रमों के साथ आवश्यक गठजोड़ प्रदान करने के लिए सब्सिडी देना।

उनकी वित्त रोजगारोन्मुख योजनाओं में (i) लघु सिंचाई सहित कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ, (ii) लघु उद्योग, (iii) परिवहन और (iv) व्यापार और सेवा क्षेत्र शामिल हैं। वे एनएसएफडीसी बैंकों से ऋण घटक को अपने स्वयं के धन से मार्जिन मनी और विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए) से बाहर सब्सिडी के साथ परियोजनाओं को वित्तपोषित करते हैं।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एंव विकास निगम

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त एंव विकास निगम की स्थापना 1989 में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा–8 (पूर्व में कंपनी अधिनियम 1956 की धारा–25) के तहत लाभ के लिए नहीं कंपनी के रूप में की गई थी ताकि गरीबी रेखा से दोगुनी नीचे जीवन यापन करने वाले लाभार्थी अनुसूचित जाति और सकें इसने मुख्य रूप से जून 2000 से सूक्ष्म ऋण योजना को शामिल करके लाभाथयों के कवरेज को कई गुना बढ़ा दिया है।

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम

सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता मंत्रालय (सामजिक न्याय एंव अधिकारिता मंत्रालय) के अधीन भारत सरकार के उपक्रम एनएसकेएफडीसी की स्थापना 24 जनवारी, 1997 को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत लाभ के लिए नहीं कंपनी के रूप में की गई थी कंपनी अधिनियम,2013 की तत्मालीन धारा 25 ।ह अक्टूबर 1997 से पूरे भारत में सफाई कर्मचारियो ंं(कचरा बीनने वालों सहित), मैला ढोने वालों और उनके आश्रितों के सर्वागीण सामाजिक–आर्थिक उत्थान के लिए एक शीर्ष निगम के रूप में संचालित हो रहा है। इसकी ऋण स्कीमें राज्य सरकारों /संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा नामित राज्य चैनलाइजिंग एजेसियों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती हैं। विभिन्न एनएसकेएफडीसी योजनाओं के अंतर्गत

लक्षित समूहों को वित्तीय सहायता स्वीकृति और जारी करने के लिए एससीए/आरआरबी/राष्ट्रीयकृत बैकों को रियायती ब्याज दरों पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

अनुसूचित जातियों के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान

अनुसूचित जातियों के लिए काम करने वाले स्वैच्छिक संगठनों के लिए सहायता अनुदान की योजना का उद्देश्य शैक्षिक मानकों में सुधार करना और कौशल का उन्नयन करना है ताकि उन्हें स्वरोजगार या वाणिज्यिक और अन्य उद्यमों के साथ नियमित रोजगार प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके। यह अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए स्कूल और छात्रावास खोलने, व्यावसायिक प्रशिक्षण या किसी अन्य आय सृजन कौशल के लिए दिया जाता है। अनुसूचित जाति परिवारों के बच्चों की देखभाल के लिए बालवाड़ी और बाल केंद्र चलाने के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है, जब उनके माता–पिता काम के लिए दूर होते हैं। अनुसूचित जाति के परिवारों की सघनता वाले क्षेत्रों में मोबाइल सहित अस्पताल और औषधालय स्थापित करके चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

मैला ढोने वालों और उनके आश्रितों की मुक्ति और पुनर्वास की राष्ट्रीय योजना (एनएसएलआरएस)

1991–92 में मैला ढोने वालों को रात की मिट्टी और गंदगी को मैन्युअल रूप से संभालने के लिए वैकल्पिक रूप से उनके प्रशिक्षण और पुनर्वास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था।

एनएसएलआरएस टीआरवाईएसईएम मानदंडो के अनुसर सरकार, स्थनीय निकायों और गैर–सरकारी संगइनों द्वारा संचलित संस्थानों में प्रशिक्षण के लिए सहायता प्रदान करता है। इसमें कच्चे माल की लागत, टूल किट के लिए भत्ता आदि शामिल हैं। भारत सरकार पूरी सब्सिडी 100% अनुदान के रूप में प्रदान करती है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग

संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत 12 मार्च 1992 को अधिनियमित 65वें संवैधानिक संशोधन के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए वैधानिक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई है। यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों की निगरानी करने और उनके कल्याण से संबंधित मुद्दों की समीक्षा करने के लिए एक उच्च स्तरीय स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। संविधान के अनुच्छेद 338 का खंड (5) आयोग को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हितों की रक्षा, सुरक्षा और बढ़ावा देने के लिए व्यापक शक्तियां प्रदान करता है। इसी अनुच्छेद का खंड (8) आयोग को एक मुकदमे की कोशिश करने, भारत के किसी भी हिस्से से किसी भी व्यक्ति की उपस्थिति को बुलाने और लागू करने और शपथ पर जांच करने, हलफनामे पर साक्ष्य प्राप्त करने के साथ–साथ एक सिविल कोर्ट की शक्तियों के साथ प्रदान करता है। संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाने वाली समितियों की सिफारिशों पर की गई या प्रस्तावित कार्रवाई की व्याख्या करने वाला ज्ञापन। आयोग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का व्यापक दौरा करता है और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन, सुरक्षात्मक कानूनों, आरक्षण नीति आदि का मूल्यांकन करता है। वे संबंधित मामलों पर कई पीएसयू, वित्तीय संस्थानों, विश्वविद्यालयों और अन्य

सार्वजनिक वित्त पोषित संस्थानों द्वारा की गई कार्रवाई की भी समीक्षा करते हैं।

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग

सफाई कर्मचारीयों के हितों और अधिकारो को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम, 1993 के प्रावधानों के तहत बार 12 अगस्त 1994 को राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किया गया था इसे सफाई कर्मचारियों के कल्याण के लिए कार्यक्रमों और मामलों की जांच करने का अधिकार दिया गया है। कर्मचारियों को प्रभावित करने वाले सभी प्रमुख नीतिगत मामलों पर इसकी सलाह ली जाती है। यह केंद्रीय मंत्रालयों के साथ त्रैमासिक बैठकें करता है और सफाई कर्मचारियों के कल्याण से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करता है।

सरकारी सेवाओं में सीटों का आरक्षण

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रतिशत 1943 से बदल रहा है। सरकारी सेवाओं में आरक्षण तय करने के लिए अपनाए गए बुनियादी मानदंडों में से एक राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर कुल जनसंख्या में एससी और एसटी आबादी का अनुपात है। पदों और संवाओं में भर्ती के मामले में अनुसूचित जातियों के लिए सीधी भर्ती से भरी गई रिक्तयों का मौजूदा आरक्षण 15 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5 प्रतिशत है। अखिल भारतीय आधार पर खुली प्रतियोगिता के माध्यम से या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा आयोजित खुली प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से बनाया गया है।

13.5 अन्य वर्गों के साथ अनुसूचित जातियों का एकीकरण

जाति व्यवस्था अभी भी काफी कठोर है, खासकर ग्रामीण इलाकों में। इसलिए, एक अनुसूचित जातियों को समाज के अन्य वर्गों के साथ एकीकृत करने के लिए बहु–स्तरीय और बहु–आयामी प्रयासों की आवश्यकता है। शिक्षा, मीडिया– विशेष रूप से टेलीविजन, स्वैच्छिक संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और धार्मिक नेताओं को अस्पृश्यता, सामाजिक भेदभाव और जातिवाद के खिलाफ सामान्य जागरूकता पैदा करने में सक्रिय रूप से शामिल होना चाहिए।

मुझे आपकी प्रगति की जांच करने दें। फिर, हम अनुसूचित जनजातियों और उनके विकास पर चर्चा करने के लिए आगे बढ़ते हैं।

13.6 अनुसूचित जनजातियाँ कौन हैं?

जनजाति, जिसे भारत में 'एनिमिस्ट', 'आदिवासी' और 'आदिवासी' भी कहा जाता है, को पहाड़ियों और जंगलों में रहने वाले अर्ध–सभ्य लोगों के रूप में माना जाता है या कृषकों के एक विशेष समूह के रूप में माना जाता है। जनजाति लोगों का एक क्षेत्रीय समूह है, जिनकी अपनी भाषा, धर्म, संस्कृति और एकीकृत सामाजिक संगठन है। इसमें आमतौर पर कई सिब, बैंड, गांव या अन्य विशेष समूह शामिल होते हैं।

आदिवासियों को भारत का मूल निवासी माना जाता है, जो विदेशी समुदायों के आक्रमणों और अधिक शक्तिशाली पड़ोसी समुदायों के लगातार दबाव के कारण जंगलों, पहाड़ियों और अन्य दुर्गम क्षेत्रों में ले जाया गया था। अलग–थलग अस्तित्व में उन्होंने अपनी विशिष्ट संस्कृति, परंपराओं, भाषाओं और प्रशासनिक संरचना का विकास किया। जबकि उनमें से कुछ बसे हुए कृषक हैं, कई अन्य अभी भी झूम खेती,

शिकार, भोजन एकत्र करने आदि पर निर्भर रहें।

भारत सरकार अधिनियम 1935 ने आदिवासियों द्वारा बसाए गए अधिकांश क्षेत्रों को बहिष्कृत या आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र घोषित किया था। स्वतंत्रता के बाद, ऐसे क्षेत्रों का नाम बदलकर अनुसूचित क्षेत्र कर दिया गया और उन्हें संविधान की अनुसूची V और VI में शामिल किया गया। अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता के लिए आवश्यक विशेषताएं आदिम लक्षण, भौगोलिक अलगाव, विशिष्ट संस्कृति, बाहरी लोगों के संपर्क में शर्म और आर्थिक पिछड़ापन हैं।

'अनुसूचित जनजाति' मुख्य रूप से एक प्रशासनिक और संवैधानिक शब्द है जो संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत सूचीबद्ध एक आदिवासी समुदाय को संदर्भित करता है। , यह अनुसूचित जनजाति के रूप में ''जनजाति'' को निर्दिष्ट करने के लिए अपनाए जाने वाले सिद्धांतों या नीतियों के बारे में मौन है। अनुच्छेद 342 में कहा गया है, ''राष्ट्रपति, किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में और जहां यह एक राज्य है, वहां के राज्यपाल से परामर्श के बाद, सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा जनजातियों या जनजातीय समुदायों या उनके भीतर के हिस्सों या समूहों को निर्दिष्ट कर सकता है। जनजातियों या जनजातीय समुदायों, जो, इस संविधान के प्रयोजन के लिए, उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के रूप में समझी जाएगी,

अनुसूचित जनजातियों के रूप में जनजातियों की पहचान में कठिनाइयों के बावजूद, भारत में नीति निर्माताओं, योजनाकारों और प्रशासकों के बीच जनजातीय समुदायों के अत्यधिक सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ेपन के बारे में पूरी जागरूकता रही है। लेकिन ऐसे जनजातीय समुदायों को उनकी वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक देखभाल और सुरक्षा के रूप में पहले से ही सूचीबद्ध करने के लिए आवश्यक किसी भी सुरक्षात्मक और सुधारात्मक उपायों की शुरूआत। उनके पहले 1931 में ''आदिम जनजातियों'' के नाम से सूची तैयार की गई थी। इसके बाद, भारत सरकार अधिनियम, 1935 के तहत, भारत के प्रांतों के लिए ''पिछड़ी जनजातियों'' की एक सूची निर्दिष्ट की गई थी। वास्तव में, संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950 के तहत निर्दिष्ट जनजातियों की सूची 1935 के अधिनियम के तहत ''पिछड़ी जनजाति'' की सूची में जोड़ कर तैयार की गई थी।

अनुसूचित जनजाति के रूप में अर्हता प्राप्त करने वाली जनजातियों की पहचान करने के लिए, अनुसूचित जनजाति आयोग ने अपनी प्रश्नावली की प्रस्तावना में देखा हैः

''अनुसूचित जनजातियों को आम तौर पर इस तथ्य से भी पता लगाया जा सकता है कि वे पहाड़ियों में अलग रहते हैं और यहां तक कि जहां वे मैदानों में रहते हैं, वे एक अलग और बहिष्कृत अस्तित्व का नेतृत्व करते हैं और लोगों के मुख्य निकाय में पूरी तरह से आत्मसात नहीं होते हैं। अनुसूचित जनजातियां किसी भी धर्म की हो सकती हैं। वे जिस तरह का जीवन जी रहे हैं, उसके कारण उन्हें अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

इसी प्रकार, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियों के संशोधन पर सलाहकार समिति, लोकप्रिय रूप से 'लोकुर समिति' ने अनुसूचित जनजाति के रूप में एक जनजाति के पात्रता के परीक्षण के लिए आदिम लक्षणें, विशिष्ट संस्कृति, भौगोलिक अलगाव, बड़े पैमाने पर समाज के साथ संपर्क की शर्मिंदगी और पिछड़ेपन को महत्वपूर्ण मानदंड के रूप में लिया है।

30 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के रूप में अधिसूचित 705 जातीय समूह हैं। उनकी जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 8.6 प्रतिशत है (जनगणना 2011)। हालांकि पूरे देश में फैले हुए हैं, वे मुख्य रूप से गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, सघनता के अन्य क्षेत्र उत्तर–पूर्वी राज्य और दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ियों से सटे क्षेत्र और उत्तर–पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र हैं। भारत की कुल एसटी आबादी मुख्य रूप से उत्तर–पूर्वी राज्यों (17.8%), मध्य प्रदेश (14.69%), ओडिशा (9.2%), गुजरात (8.55%), राजस्थान (8.86%), महाराष्ट्र (10.8%) झारखंड (8.29%) और आंध्र प्रदेश (5.7%) द्वारा साझा की जाती है।

आजादी के बाद से, एसटी के लिए उपलब्ध विशेष लाभ ने कई समूहों को, यहां तक कि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच भी, यह विश्वास दिलाया है कि यदि उन्हें नामित किया जाता है तो वे अधिक लाभ का आनंद उठाएंगे। यह जनजातीय लोगों को अपनी पहचान बनाए रखने के लिए प्रोत्साहन देता है, लेकिन कई समूह, जिनकी ''आदिवासी'' स्थिति सांस्कृतिक रूप से सबसे अच्छी तरह से संदिग्ध है, को अनुसूचित जनजातियों के बीच सूचीबद्ध किया गया है, जो उनके पक्ष में राजनीतिक दल को वोट देने की उनकी क्षमता के कारण अनुसूचित जनजातियों में सूचीबदध किया गया है जो उनके पक्ष में है।

13.7 अनुसूचित जनजातियों के लिए संवैधानिक प्रावधान

यद्यपि अनुसूचित जनजातियों के लिए कई संवैधानिक प्रावधान अनुसूचित जातियों के समान है कुछ प्रावधान विशेष रूप से अनुसूचित जनजातियों के लिए हैं ये इस प्रकार हैं:

13.7.1 संवैधानिक सुरक्षा उपाय

अनुच्छेद 15 और 16 में जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख करता है, यह सुनिश्चित करने के लिए अपवाद बनाए गए हैं कि अनुसूचित जनजातियों के लिए जो किया जाना आवश्यक है वह किया जाए। उदाहरण के लिए, यद्यपि अवसर की समानता राज्य की नीति है, आरक्षण को अपवाद बनाया गया है।

अनुच्छेद 244 राज्य को अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए विशेष व्यवस्था करने में सक्षम बनाता है।

अनुच्छेद 275(1) राज्य को जनजातीय विकास के लिए उपयोग किए जाने वाले वित्तीय प्रावधानों को अलग रखने में सक्षम बनाता है।

संविधान की पांचवीं अनुसूची किसी राज्य के राज्यपाल को संसद या राज्य विधानमंडल के किसी भी अधिनियम को निलंबित करने का अधिकार देती है यदि उन्हें लगता है कि यह एसटी के हित में नहीं है। वह पूर्वव्यापी प्रभाव से भी ऐसा कर सकता है।

छठी अनुसूची एक स्वायत्त जिला–स्तरीय निकाय को उन क्षेत्रों में गठित करने में सक्षम बनाती है जहां जनजातीय लोग बड़े प्रतिशत का गठन करते हैं। यह विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए तैयार किया गया है जो कई मामलों में अद्वितीय है। क्षेत्र के जिले मिनी–स्टेट के रूप में कार्य कर सकते हैं क्योंकि उनके पास बहुत सारी वित्तीय, विधायी, कार्यकारी और न्यायिक शक्तियाँ हैं।

संविधान मुख्य रूप से अनुच्छेद 46 में निहित 'निदेशक सिद्धांतों' के कार्यान्वयन की सुविधा के लिए अनुसूचित जनजातियों के लिए कई सुरक्षा उपाय प्रदान करता है, जो पढ़ता है: ''राज्य विशेष रूप से लोगों के कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा और विशेष रूप से, अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक अन्याय और शोषण के सभी रूप से उनकी रक्षा करेंगे।

महत्वपूर्ण संवैधानिक सुरक्षा उपायों में अनुच्छेद 46 (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना), 330 (लोगों के सदन में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण), 332 (लोगों के लिए सीटों का आरक्षण) शामिल हैं। राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति), 335 (सेवाओं और पदों पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के दावे) और 339 (अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजाति के कल्याण पर संघ का नियंत्रण)।

अनुच्छेद 164 बिहार, मध्य प्रदेश और ओडिशा के प्रत्येक राज्य में जनजातीय कल्याण मंत्रालय का प्रावधान करता है जहां अनुसूचित जनजाति की आबादी बड़े पैमाने पर केंद्रित है। अपने अपने राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर संघ का नियंत्रण।

अनुच्छेद 244 उन राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन के प्रावधानों को शामिल करने के लिए संविधान में पांचवीं अनुसूची को शामिल करने का प्रावधान करता है, जिनकी जनजातीय आबादी काफी अधिक है (असम को छोड़कर)।

अनुच्छेद 275 अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने और उन्हें बेहतर प्रशासन प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को विशेष धनराशि प्रदान करने का प्रावधान करता है।

13.7.2 अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन

आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान राज्यों में 'अनुसूचित क्षेत्र' घोषित किए गए हैं। पांचवीं अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन की योजना राज्य और केंद्र सरकारों के बीच उत्तरदायित्व के विभाजन की परिकल्पना की गई है।

राज्य सरकारों को उन कानूनों की जांच के लिए जिम्मेदार बनाया गया है जो जनजातीय क्षेत्रों में विस्तार के लिए अनुपयुक्त हैं। केंद्र सरकार अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के लिए दिशानिर्देश प्रदान करती है। यह प्रशासन के स्तर को बढ़ाने और जनजातीय समुदायों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए आवश्यक धन भी प्रदान करता है। यह अनुसूचित जनजातियों के कल्याण से संबंधित मामलों में राज्य सरकारों को निर्देश देता है।

जिन राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र हैं, उन राज्यों के राज्यपालों को पाँचवीं अनुसूची के तहत केंद्रीय और राज्य कानूनों को संशोधित करने का अधिकार है ताकि उन्हें आदिवासी क्षेत्रों में लागू किया जा सके। पांचवीं अनुसूची के पैरा 5 के अनुसार, राज्यपाल को अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में भारत के राष्ट्रपति को एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने होती है।

पाँचवीं अनुसूची के पैरा 4 के अनुसार जनजातीय सलाहकार परिषद उन राज्यों में

स्थापित की गई है जिनमें अनुसूचित क्षेत्र हैं या जहां जनजातीय आबादी का बड़ा जमावड़ा है (जैसा कि पश्चिम बंगाल के मामले में है)। यह संबंधित राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और संरक्षण से संबंधित हैं। परिषद के कम से कम तीन–चौथाई सदस्य अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधि होते हैं जो राज्य की विधान सभा से या जनजातीय समुदायों के अन्य प्रतिनिधियों से लिए जाते हैं।

13.7.3 जनजातीय क्षेत्रों की सामाजिक–राजनीतिक स्वायत्तता

- अनुच्छेद 244(2) और 275(1) से जुड़ी छठी अनुसूची जनजातीय क्षेत्रों को काफी हद तक सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक स्वायत्तता प्रदान करती है। यह क्रमशः जिला परिषदों और क्षेत्रीय परिषदों के साथ स्वायत्त जिलों और स्वायत्त क्षेत्रों के निर्माण के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। ये परिषदें भूमि आवंटन, जंगलों और नहरों के पानी के उपयोग, झूम खेती के नियमन, ग्राम या नगर समितियों की स्थापना और उनकी शक्तियों, विवाह और अन्य सामाजिक रीति–रिवाजों से संबंधित कानून बनाती हैं। वे सामाजिक रीति–रिवाजों द्वारा संशोधित अखिल भारतीय नागरिक और दंड संहिता के तहत न्याय भी प्रदान करते हैं। वे प्राथमिक विद्यालय स्थापित कर सकते हैं और भू–राजस्व का आकलन और संग्रह करके और कर लगाकर धन जुटा सकते हैं। वे खनिज निकालने के लिए लाइसेंस जारी करते हैं। जिला परिषद गैर–आदिवासियों द्वारा साहूकारी और अन्य व्यापारिक गतिविधियों को विनियमित कर सकती है। क्षेत्रीय और जिला परिषदें अपने क्षेत्रों में संसदीय या राज्य कानूनों को लागू करने पर रोक लगा सकती हैं या प्रतिबंधित कर सकती हैं।

- पंचायतों का अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम (पीईएसए)

  1996 में नौ अनुसूची–V राज्य शामिल हैंय अर्थात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान। यह प्राकृतिक संसाधनों पर पारंपरिक सामुदायिक अधिकारों को मान्यता देता है, आदिवासी ग्राम सभाओं, यानी ग्राम सभाओं को गैर–इमारती वन उपज की बिक्री, भूमि का अधिग्रहण आदि जैसे मामलों पर अधिकार देता है और खनन क्षेत्र में ग्राम सभाओं को एक बड़ी भूमिका प्रदान करता है। पर्यावरण मंजूरी के लिए परामर्श करने की आवश्यकता है।

- इसके अलावा, वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) 2006 अनुसूचित जनजातियों को उनके प्राकृतिक संसाधनों के अधिकारों को स्वीकार करके अनुसूचित जनजातियों को और अधिक सशक्त बनाता है।

  प्राकृतिक आवास। इनके साथ–साथ, केंद्र सरकार और राज्यों दोनों से निर्धारित विकास निधियां जो जनजातीय उप–योजना (टीएसपी) नामक एक विशेष बजटीय साधन के माध्यम से जनजातीय क्षेत्रों में प्रवाहित होती हैं।

- 1999 में स्थापित विशेष जनजातीय मामलों का मंत्रालय, अनिवार्य रूप से, अनुसूचित जनजातियों की भलाई सुनिश्चित करने में एक नोडल मंत्रालय की भूमिका निभा रहा है। इस विशेष कार्य को निष्पादित करने में, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, जो एक प्रहरी के रूप में काम करता है और व्यक्तिगत मुद्दों की जांच के अलावा आदिवासियों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए कड़ी निगरानी रखता है।

- एक विशेष राष्ट्रीय वित्त और विकास निगम एसटी के लिए 2001 से काम कर रहा है। यह निकाय, राज्य–स्तरीय जनजातीय विकास निगमों के साथ, आदिवासियों की आर्थिक बेहतरी के लिए विभिन्न आय और रोजगार–सृजन गतिविधियों का समर्थन करने में मंत्रालय की सहायता करता है।

13.8 अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति

भारत में, आदिवासी क्षेत्र देश के अविकसित क्षेत्रों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। लगभग 93 प्रतिशत जनजातियाँ ग्रामीण क्षेत्रों में रहती हैं और कृषि और संबद्ध गतिविधियों में लगी हुई हैं। एसटीएस दूसरों की तुलना में वंचित हैं। एसटी के लिए 59 प्रतिशत की साक्षरता दर पूरे भारत के लिए 72.8 प्रतिशत की राष्ट्रीय साक्षरता दर (जनगणना 2011) से कम है।

ऐतिहासिक रूप से, अधिकांश जनजातियाँ निर्वाह कृषि या शिकार और संग्रहण में लगी हुई हैं। हालाँकि, बीसवीं शताब्दी ने बड़े समाज के साथ आदिवासियों के संबंधों में दूरगामी परिवर्तन देखे हैं, और विस्तार से, पारंपरिक जनजातीय अर्थव्यवस्थाओं में। बेहतर परिवहन और संचार ने जनजातीय भूमि में गहरी घुसपैठ की हैय व्यापारियों और विभिन्न प्रकार की सरकारी नीतियों ने जनजातीय लोगों को नकद अर्थव्यवस्था में अधिक अच्छी तरह से शामिल किया है, हालांकि, किसी भी तरह से, अनुकूल शर्तों पर नहीं।

1900 ई. के आसपास बड़े क्षेत्र गैर–आदिवासियों के हाथों में आ गए, जब कई क्षेत्रों को सरकार द्वारा वास–शैली की बसावट के लिए खोल दिया गया। इन–प्रवासियों को इसकी खेती के बदले में मुफ्त जमीन मिली। जनजातीय लोग भी, भूमि स्वामित्व के लिए आवेदन कर सकते थे, हालांकि भूमि के हिस्से का शीर्षक भी स्थानांतरित खेती जारी रखने की उनकी क्षमता की गारंटी नहीं दे सकता था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि भूमि के स्थायी व्यक्तिगत स्वामित्व की धारणा अधिकांश आदिवासियों के लिए विदेशी थी। जब तक, आदिवासियों ने औपचारिक भूमि स्वामित्व प्राप्त करने की आवश्यकता को स्वीकार कर लिया, तब तक वे उन भूमियों पर दावा करने का अवसर खो चुके थे, जिन्हें उचित रूप से उनका माना जा सकता था। आम तौर पर, सरकारी अधिकारियों के साथ व्यवहार करने में आदिवासियों को गंभीर रूप से वंचित किया जाता था, जिन्होंने भूमि का अधिकार दिया था।

देर से सही, औपनिवेशिक शासन ने आदिवासियों को बाहरी बाहरी लोगों से बचाने की आवश्यकता को महसूस किया और आदिवासी भूमि की बिक्री पर रोक लगा दी। हालांकि भूमि पट्टों के रूप में एक महत्वपूर्ण बचाव का रास्ता खुला छोड़ दिया गया था, लेकिन जनजातियों ने बीसवीं शताब्दी के मध्य में कुछ लाभ कमाया। स्थानीय पुलिस और भूमि अधिकारियों द्वारा काफी बाधा डालने के बावजूद, जो आदिवासी जोत को चित्रित करने में धीमे थे और पुलिस सुरक्षा प्रदान करने में भी धीमे थे, कुछ भूमि आदिवासियों लोगों को वापस कर दी गई थी।

1970 के दशक में जनजातीय लोगों के पहले के दशकों में किए गए लाभ कई क्षेत्रों में, विशेष रूप से मध्य भारत में, जनजातीय भूमि में नाटकीय रूप से वृद्धि के कारण समाप्त हो गए थे। कांस्टेबुलरी और राजस्व अधिकारियों का घातक संयोजन, आदिवासी कल्याण में कोई दिलचस्पी नहीं, और परिष्कृत गैर–आदिवासी, स्थानीय अधिकारियों को रिश्वत देने के इच्छुक और सक्षम, कई आदिवासियों को उनकी भूमि

से वंचित कर दिया। सुरक्षात्मक कानून को कई तरीकों से उलट दिया गया था: स्थानीय अधिकारियों को गैर–आदिवासी लोगों द्वारा भूमि–अधिग्रहण की उपेक्षा करने, भूमि रजिस्ट्री रिकॉर्ड में बदलाव करने, छोटी अवधि के लिए भूमि के भूखंडों को पट्टे पर देने और फिर उन्हें छोड़ने से इनकार करने, या आदिवासी सदस्यों को बनने के लिए प्रेरित करने के लिए राजी किया जा सकता था। कर्जदार हैं और अपनी जमीन कुर्क करते हैं। परिणामस्वरूप, 1960 और 1970 के दशक में कई आदिवासी भूमिहीन मजदूर बन गए और विशेष जनजातीय क्षेत्र तेजी से विषम हो गए।

13.9 अनुसूचित जनजातियों के लिए किए गए अधिकारिता उपाय

भारत में एसटी के विकास के विभिन्न स्तर हैं। 1960 के दशक में जनजातीय विकास समूहों की स्थापना की गई, जो लक्ष्य–उन्मुख योजनाओं के साथ धीरे–धीरे आगे बढ़े। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना एक विशेष योजना थी जिसमें जनजातीय सघनता वाले क्षेत्रों और उनमें प्राकृतिक संसाधनों की पहचान करने, परियोजनाएँ तैयार करने, उनके लिए वित्तीय संसाधन खोजने और उन्हें लागू करने के लिए कदम निर्धारित किए गए थे। छठी योजना में, 180 एकीकृत विकास परियोजनाओं को चार गुना जोर: स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक विकास और बुनियादी ढांचे के साथ स्थापित किया गया था। विभिन्न समुदायों के सांसदों, विधायकों और अन्य आदिवासी नेताओं को शामिल करते हुए आदिवासी दमन की रणनीति पर काम किया गया।

13.9.1 जनजातीय विकास में राज्य की भूमिका

अनुच्छेद 46 राज्य को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े समूहों की रक्षा करने और उनके विकास के लिए साधन प्रदान करने का निर्देश देता है। इसलिए, 1951 में नियोजित युग की शुरुआत से ही आदिवासी विकास के प्रयास किए गए थे।

चूँकि भारत की अधिकांश जनसंख्या गाँवों में निवास करती रही है, इसलिए प्रत्येक योजना में ग्रामीण पुनर्निर्माण पर विशेष बल दिया गया। हालाँकि, इसे शुरू में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के माध्यम से हासिल करने की कोशिश की गई थी। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए 1952 में पहली योजना में 52 परियोजनाएं शुरू की गईं। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास और आत्मनिर्भर विकास के लिए एक नया जोर देने के लिए सामुदायिक विकास ब्लॉकों की परिकल्पना की गई थी। ब्लॉकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए सेवाओं की एक विस्तृत स्पेक्ट्रम की शुरुआत की। विभिन्न योजनाओं के आरेखण एवं क्रियान्वयन के लिए प्रखंडों को उचित दिशा देने तथा विकास में जनभागीदारी एवं भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु जिला सलाहकार समितियों का गठन किया गया. आदिवासी क्षेत्रों में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के लिए विशेष प्रयास और अधिक वित्तीय निवेश करने के लिए, 1954 में इस कार्यक्रम को आदिवासी क्षेत्रों तक विस्तारित करने का निर्णय लिया गया, जिसमें शुरू में ऐसे 43 ब्लॉकों का चयन किया गया था।

13.9.2 जनजातीय विकास खंड

बाद में, जनजातीय विकास का एक कम गहन और अधिक व्यावहारिक दृष्टिकोण जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए सामुदायिक विकास खंडों की तुलना में ब्लॉकों की शुरुआत की गई थी। हालाँकि, आदिवासी विकास खंडों को सामुदायिक विकास

खंडों की तुलना में छोटे भौगोलिक क्षेत्रों और कम आबादी की सेवा की आवश्यकता थी। उन सभी क्षेत्रों को जनजातीय विकास खंडों के दायरे में लाया गया जहां जनजातीय आबादी दो तिहाई है। तीसरी योजना के अंत तक, 500 से अधिक ऐसे जनजातीय विकास खंड थे, जो भारत की कुल जनजातीय आबादी के लगभग 40 प्रतिशत की सेवा कर रहे थे।

चौथी योजना के दौरान योजना आयोग द्वारा गठित शिलो एओ समिति ने पांचवीं योजना की पूर्व संध्या पर जनजातीय विकास के दृष्टिकोण और रणनीति की व्यापक समीक्षा की। इसने अवगत कराया कि जनजातीय विकास के एक साधन के रूप में जनजातीय विकास खंड, आदिवासियों की जटिल समस्याओं से निपटने के लिए अनुपयुक्त थे और यह भी नोट किया कि जनजातीय समस्याओं को हल करने के लिए कोई भी कार्यक्रम पर्याप्त नहीं था। अधिक जनजातीय सघनता वाले क्षेत्रों की समस्याएँ बिखरी हुई जनजातीय आबादी के क्षेत्रों से भिन्न हैं, विशेष रूप से संसाधनों के स्वामित्व के संदर्भ में। बेहतर संचार और अन्य सुविधाओं के कारण पिछले कुछ वर्षों में जनजातीय सघनता वाले क्षेत्रों का बाहरी दुनिया के साथ संपर्क बढ़ा है, जो उनके संसाधन स्वामित्व पैटर्न को आंशिक रूप से प्रभावित कर रहा है। दूर–दराज के क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समूहों के पास सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न जाँचों और नियंत्रणों के कारण आर्थिक संसाधनों पर बहुत सीमित नियंत्रण है। इन बिखरे हुए जनजातीय समुदायों में से अधिकांश पिछड़े, जैसे ओंगे, बिरहोर या अबूझमारिया अभी भी एक पूर्व–कृषि अवस्था में हैं और शिकार, मछली पकड़ने या भोजन एकत्र करने के माध्यम से जीवित हैं।

13.9.3 जनजातीय उप–योजना

विभिन्न आदिवासी क्षेत्रों की समस्याओं को प्रभावी ढंग से हल करने के लिए पांचवीं योजना के तहत विकास का एक व्यापक कार्यक्रम, आदिवासी उप–योजना तैयार की गई। तदनुसार, 50 प्रतिशत से अधिक जनजातीय आबादी वाले सभी क्षेत्रों को उप–योजना क्षेत्र माना गया। हालाँकि, औद्योगिक और शहरी परिक्षेत्रों को इसके दायरे से बाहर रखा गया था। एक विकास खण्ड को विकास की सबसे छोटी इकाई के रूप में लिया गया। तहसील (आमतौर पर कई ब्लॉक शामिल हैं) को योजना और विकास के लिए बुनियादी इकाई के रूप में लिया गया था। इस कार्यक्रम को एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना (आईटीडीपी) के रूप में जाना जाता है।

आईटीडीपी में 17 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों को कवर किया, जिसमें 26 जिले पूरी तरह से और 97 जिले आंशिक रूप से शामिल थे। यह आदिवासी बहुल राज्यों और मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, दादरा और नगर हवेली और लक्षद्वीप के केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित नहीं है क्योंकि उनकी संबंधित योजनाएं मुख्य रूप से स्थानीय आदिवासी आबादी के विकास के लिए हैं। हाल के दिनों में अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए यह एक प्रमुख साधन रहा है।

13.9.4 जनजातीय विकास के लिए नीतियां और कार्यक्रम

अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास के लिए दो राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना की गईय अर्थात, (i) आदिवासी सहकारी विपणन विकास संघ (ट्राइफेड) 1987 में राज्य आदिवासी विकास सहकारी निगमों के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में और (ii) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति पूर्व में आदिवासियों के वन और कृ षि उपज के लिए पारिश्रमिक मूल्य प्रदान किया जाता है जबकि बाद में रोजगार

सृजन के लिए ऋण सहायता प्रदान की जाती है। बाद की योजनाओं ने अनुसूचित जनजातियों और समाज के अन्य वर्गों के बीच विकास की खाई को पाटने के प्रयासों को तेज कर दिया।

13.10 आदिवासियों के अनसुलझे मुद्दे और स्थायी समस्याएं

नियोजित विकास ने बांधों, खानों, उद्योगों और सड़कों को जन्म दिया, जो सभी आदिवासी भूमि पर स्थित थे। बदले में, उन्होंने विस्थापन की सहवर्ती प्रक्रियाओं को उत्पन्न किया, जिसके बाद विकास और जनजातीय अधिकारों और हितों के बीच संघर्ष हुआ। इस प्रकार, विकास समस्याग्रस्त हो गया।

13.10.1 आदिवासियों का विस्थापन

आदिवासियों का उनकी भूमि या उनके प्राकृतिक आवास से विस्थापन या जबरनध्स्वैच्छिक बेदखली और उसके बाद उनके पुनर्वास की समस्या का समाधान किया जाना बाकी है। 1951—1990 की अवधि में, मुख्य रूप से विकास परियोजनाओं को लागू करने के लिए आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा राज्यों में 21.3 मिलियन लोग विस्थापित हुए थे। उनमें से, 8.54 मिलियन (40 प्रतिशत) आदिवासी हैं, जिनमें से अब तक केवल 2.12 मिलियन (24.8 प्रतिशत) आदिवासियों का ही पुनर्वास किया जा सका है। अधूरे पुनर्वास ने उन्हें बढ़ती बेरोजगारी, कर्ज बंधन और अभाव के भंवर में धकेल कर उनकी समस्याओं को और बढ़ा दिया है।

13.10.2 जनजातीय भूमि (अलगांव) हस्तांतरण

भूमि आदिवासियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक संसाधन होने के साथ—साथ उनकी सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं का मुख्य आधार है। यह उनके मानस में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। समय के साथ, यह संसाधन आधार सार्वजनिक उद्देश्य के लिए इसके अधिग्रहण के माध्यम से और धोखाधड़ी के हस्तांतरण, जबरन बेदखली, बंधक, पट्टे और अतिक्रमण के माध्यम से भी कम हो गया है। राजनीतिक और प्रशासनिक इच्छाशक्ति की कमी ने आदिवासियों की भूमि हस्तांतरण की समस्या को चिरस्थायी बना दिया है। यह कानूनी प्रावधानों में संशोधन करने और मौजूदा खामियों को दूर करने, और हस्तांतरित भूमि की पहचान करने और उन्हें वापस करने के लिए तेजी से प्रशासनिक कार्रवाई करने की अनिच्छा को दर्शाता है।

13.11 आइए संक्षेप करें

आजादी के बाद से, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का विकास भारतीय राज्य के एजेंडे में रहा है। ऐतिहासिक रूप से सबसे पिछड़ा वर्ग होने के नाते, वे समाज में वंचित स्थिति में हैं। अनुसूचित जाति जाति की सीढ़ी पर सबसे निचले पायदान पर रही है जबकि अनुसूचित जनजाति दूरस्थ और वंचित क्षेत्रों में अलग—थलग रहती है। संविधान ने उनके संरक्षण और विकास के लिए प्रावधान किया है और सरकार ने उनके सशक्तिकरण के लिए कई उपाय किए हैं। हालाँकि, उनके लगातार मुद्दे देश में कई सामाजिक आंदोलनों में प्रकट हुए हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए क्रमशः सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और जनजातीय मामलों के मंत्रालय के दृष्टिकोण ने हाल के वर्षों में कुछ परिणाम दिए हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है।

उनकी समस्याओं के समाधान के लिए।

13.12 प्रमुख शब्द

एनएसएफडीसी : राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम की स्थापना 1989 में लाभ के लिए नहीं कंपनी के रूप में की गई थी।

अनुसूचित क्षेत्र : संविधान की पांचवीं अनुसूची के तहत घोषित आदिवासी आबादी वाला क्षेत्र।

भूमि अलगाव : सार्वजनिक उददेश्यों के लिए अधिग्रहरण के माध्यम से या धोखाधड़ी वाले हस्तांतरण, जबरन बेदखली, बंधक, पट्टे और अतिक्रमण के माध्यम से आदिवासियों के बीच भूमि का नुकसान।

3.13 सुझाई गई अध्ययन

चौरसिया, बी.पी. (1990). अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। इलाहाबादः चुघ प्रकाशन।

भारत सरकार। वार्षिक रिपोर्ट 2019–20। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोगः एक पुस्तिका, 1997. नई दिल्ली।

पति, आर.एन. और जेना, बी (1989)। भारत में जनजातीय विकास नई दिल्लीः आशीष पब्लिशिंग हाउस।

राय, रामाश्रय. (1999)। दलित, विकास और लोकतंत्र। शिप्रा प्रकाशन।

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY